बिहार विधान सभा वादवृत्त

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार तिथि, २३ अप्रिल, १९५४ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

Short Notice Questions and Answers.

सरकारी दफ्तर का मकान।

४२६। श्री खूबलाल महतो—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि हरावत इस्टेट (सहरसा जिला के अन्तर्गत) सरकार के कब्जे में चला आया है;

(ख) क्या यह बात सही है कि इस इस्टेट का हेड ऑफिस तथा तहसील ऑफिस गनपतगंज में है जिसको खाली कर २९ जुलाई १९५२ को सरकार में दे देने के लिये मालिकों ने लिखकर वादा किया था और वह खाली पड़ा हुआ है;

(ग) क्या यह बात सही है कि वह इतना बड़ा मकान है कि उसमें स्थानीय सब-रजिस्ट्रार तथा सर्कल ऑफिस का काम आसानी से चल सकता है;

(घ) क्या सरकार स्थानीय सब-रजिस्ट्री ऑफिस तथा सर्कल ऑफिस का नया मकान नहीं बनाकर हरावत इस्टेट के मकान को काम में लाने का विचार रखती है;

(ङ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो इस संबंध में कहां तक कार्रवाई हुई और आगे सरकार क्या करने जा रही है?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(क) उत्तर हां है।

(ख) हरावत इस्टेट का हेड आफिस गनपतगंज के मकान में रखा गया है। प्रोप्राइटर का कहना है कि वे इस बिल्डिंग को रहने के काम में इस्तेमाल करते थे, मालगुजारी वसूल करने के काम में नहीं। प्रोप्राइटर ने कभी वादा नहीं किया था कि वे गनपतगंज के मकान को राज्य सरकार को दे देंगे। गनपतगंज का मकान अभी खाली पड़ा हुआ है।

(ग) इसका उत्तर हां है।

(घ) सरकार के सामने एक प्रस्ताव था कि हरावत इस्टेट के मैनेजर का मकान किराया पर लिया जाय जिसमें स्थानीय सब-रजिस्ट्रार तथा सर्किल आफिस रहे लेकिन मैनेजर ने इस मकान को किराये पर देने से इन्कार कर दिया है और इसलिये इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है। सर्किल आफिस के बारे में यह आदेश जारी किया गया कि उस ऑफिस को प्रतापगंज में ले जाया जाय। एक नया मकान इस दफ्तर के लिये बनवाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं है।

(ङ) यह सवाल नहीं उठता है।

ADJOURNMENT MOTION :

मुजफ्फरपुर शहर में विद्युत का समायोजन ।

SUPPLY OF ELECTRICITY TO MUZAFFARPUR TOWN.

SPEAKER : There is one adjournment motion tabled by Shri Nitishwar Prasad Sinha which is as follows :—

I beg to move that the House do adjourn to discuss a definite matter of urgent public importance, viz., "failure of the Government to ensure supply of electricity in this extraordinarily hot month to the citizens of Muzaffarpur in view of the decision of the Muzaffarpur Electric Supply Company, Ltd., Muzaffarpur, to cut down supply of electricity to Muzaffarpur town on 21st April 1954".

SPEAKER : I would like first to hear the hon'ble member in support of the admissibility of his motion.

*श्री नीतिश्वर प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर बिजली कंपनी ने यह नोटिस दी है कि ३१ ता० से १२ घंटे बिजली बंद रहेगी । इस कारण मुजफ्फरपुर की अवस्था बड़ी भयानक है । व्यापार में हर तरह की गंभीर समस्याएं आ जाने का डर है । इसी तरह अनेकों काम में बाधा होगी जो मनुष्य के जीवन और मरण का प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय, ६ वर्षों से बिजली सप्लाई की समस्या की बात आ रही है जिसमें बिहार राज्य की ओर से हमेशा आश्वासन दिया गया कि बिजली कंपनी को राष्ट्रीयकरण किया जायगा । परन्तु यह आश्वासन केवल बिहार की जनता को संतोष देने ही के लिए दी जाती है । आज तक इसे पूरा करने की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया ।

मुजफ्फरपुर बिजली कंपनी को १० लाख रुपये कर्ज दिये गये परन्तु उस रुपये को बिजली की उन्नति में न लगाकर दूसरे-दूसरे कामों में लगा दिया गया । अध्यक्ष महोदय, तो बतलाया जाय कि किस तरह बिजली में सुधार हो सकता है । एक बार जब हमारे सिंचाई मंत्री कांफ्रेंस में मुजफ्फरपुर गये थे तो वहां बोले थे कि आप इस तरह की छोटी-छोटी बातों के बारे में क्या पड़े हुए हैं । उन्होंने यह भी कहा था कि गंगा के पानी की तरंगों से बिजली पैदा करके सारे शहर को जगमगा दिया जायगा । आप इसके लिए क्यों चिन्ता महसूस करते हैं । परन्तु यह बड़े दुख: की बात है कि चकिया मोतिहारी जिले में आपने बिजली उत्पादन का मशीन बैठाया जिसकी लाइन इतनी दूर पर आ गई है कि जहां से मुजफ्फरपुर की दूरी लगभग १० मील की है । उसी तरह समस्तीपुर और हाजीपुर लाइन में भी बिजली की लाइन उस स्थल तक आगई है जहां से मुजफ्फरपुर की दूरी करीब १० मील है । बहुत आश्चर्य की बात है कि इस अवस्था में सरकार इन बिजलियों से मुजफ्फरपुर शहर को बिजली क्यों नहीं देती है । जहां तक इन बिजली मशीनों का प्रश्न है मेरा विश्वास है कि बहुत सी बिजली बेकार जाती है जिसको एकत्र करके मुजफ्फरपुर शहर की इस बिजली क दिक्कत को सरकार दूर कर सकती है । सरका की ओर से कई बार इस सदन में विश्वास दिलाया गया कि मुजफ्फरपुर बिजली कंपनी का नियंत्रण सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है लेकिन अभी तक सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया है । ज्यों ज्यों मर्ज की दवा सरकार ने की मर्ज बढ़ता ही गया और जब इस अवस्था में बिजली कंपनी के अधिकारियों

ने २१ अप्रैल से बिजली ग्राहकों को तथा अति आवश्यक कार्यों में बारह-बारह घंटे की कटौती करके मुजफ्फरपुर शहर की परिस्थिति को नाजुक बना दिया है। बिजली की कमी के कारण अस्पताल में रोगी के मरने और जीने का प्रश्न गंभीर हो गया है इस गर्मी के जमाने में पानी के कारण मनुष्य तड़प-तड़प कर मरेगा। बहुत से कॉलेजों की पढ़ाई बंद की जा रही है। अब इससे अधिक भयानक अवस्था मानव जीवन की क्या हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि वर्त्तमान बिजली कंपनी की प्रवृत्ति सुधार करने की नहीं है। भारत सरकार के फाइनेंस कारपोरेशन की ओर कुछ लोन देने की बात-चीत हुई थी लेकिन कंपनी ने भीतर-भीतर ऐसी कार्रवाई की कि उसने लोन नहीं लिया। यही नहीं इस बीच में कंपनी ने कई नई मशीनें खरीद की। लेकिन उन मशीनों को मुजफ्फरपुर में प्रयोग न कर दूसरे स्थानों में भेज दिया और कुछ मशीनों को कंपनी ने बेच दिया। इससे कंपनी की नीति का पता लगता है। इस तरह फिर बिहार राज्य से कर्ज देकर कंपनी में कोई सुधार हो ऐसी झलक नहीं आ रही है। जबकि कंपनी की नीति इसको सुधारने की नहीं है तो सिर्फ कर्ज देने से परिस्थिति कैसे संभल सकती है। बिहार राज्य को चाहिए कि इस कंपनी को अपने अधीन में शीघ्र ले और मुजफ्फरपुर की जनता के कष्ट को दूर करें। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त बातों से आज की इस ऐडजोर्नमेंट मोशन की महत्ता भलि भांति प्रगट होती है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस ऐडजोर्नमेंट मोशन पर विचार करने की अनुमति दें।

SPEAKER : The Hon'ble Minister for Electricity may also have his say.

Shri RAMCHARITRA SINHA : Sir, I say that the situation has been deteriorating for the last four years, but the hon'ble member has said that it has been deteriorating for the last six years. This argument is in itself a proof of the fact that this is not a fit case for an adjournment motion because nothing has happened suddenly.

SPEAKER : It cuts both ways. Does not the Hon'ble Minister's statement suggest that Government have not been taking action for the last four years ?

Shri RAMCHARITRA SINHA : The point at issue is that it not covered by the rules regarding adjournment motions. But, Sir, if you permit me I may read before the House a statement on the subject.

SPEAKER : Yes.

Shri RAMCHARITRA SINHA : The supply position at Muzaffar-pur has been steadily deteriorating for the last three or four years. Several conferences were held with their Managing Directors and Engineers to explore ways and means for improving supplies. Their difficulties were reported to be due to heavy cost of running and the Company was sustaining continued loss and was not in a position to spent any further capital on additional generating sets. As a result, after much correspondence, the Company agreed to hand over the Electric Supply to the Government at their book value and a

scheme was put up to Government and approved, costing about Rs. 18 lakhs for improving supplies. This was included in the First Five-Year Plan and was proposed to be implemented during the last two years. But when the proposal went to the Government of India, they discouraged acquisition of private licensees as a matter of policy and advised Government to assist the company financially so that they can resuscitate their undertaking without Government having to acquire the undertaking.

Based on this advice of the Government of India a loan of Rs. 10 lakhs has been sanctioned for the Company a few weeks ago.

The company has already placed orders for two large sets which are expected to be received in three to four months time and will go into commission within 7 months. In the meantime they have arranged for sufficient spares for overhauling the four existing generating sets and the work of repairs will be put in hand immediately. Pending these repairs the position of the generating sets at Muzaffarpur is causing serious anxiety and it has become necessary to restrict loads and certain restrictions are being enforced by the Electrical Company with the Concurrence of the Government.

But as several difficulties have been raised by the local consumers and also by the Commissioner, the Electrical Inspector has been sent to Muzaffarpur and he is camping there since yesterday, and will contact local important consumers and also the Commissioner and the District Magaistrate and will make such modifications as are possible so that inconvenience to the public is minimised as far as possible.

श्री नीतिश्वर प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के भाषण में कई बातों

का स्पष्टीकरण नहीं हुआ। २१ अप्रील से बिजली बंद करने की जो नोटिस कंपनी ने जारी की है उस के मुताबिक हौस्पिटल में रोशनी तथा पानी बंद हो जायेगा। आप खुद समझ सकते हैं कि इस गर्मी के दिनों में पानी और रोशनी का बंद हो जाना कितनी दिक्कत की बात है। जब छः वर्षों से स्थिति खराब हो रही है फिर भी आज तक सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिये कोई निश्चित उपाय काम में नहीं लाया।

इस कारण अस्पतालों में बिजली नहीं मिली और जिनकी दवा बिजली के द्वारा हो सकती थी उनको मौत के घाट उतरना होगा.....।

अध्यक्ष—शांति, शांति। एलेक्ट्रिक इंसपेक्टर का भेजा जाना कोई व्यवस्था नहीं है?

श्री नीतिश्वर प्रसाद सिंह—वह तो कई बार जा चुके। लोन भी कई बार कंपनी

ने लिया। मशीन भी खरीदी गई लेकिन वह दूसरी जगह भेज दी गई और इससे यही मालूम होता है कि उसका वहां काम करने का इरादा नहीं है।

अध्यक्ष—आप मेरिट्स में न जायें।

श्री नीतिश्वर प्रसाद सिंह—मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्यों ज्यों दर्द की दवा की दर्द बढ़ता ही गया। अब वहां कॉलेज भी बंद होने जा रहा है। १० लाख कर्ज दिया गया और मशीन भी खरीदी गई लेकिन वह दूसरी जगह जैसा मैंने अभी कहा भेज दी गई।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री ने कहा कि मशीन के लिए ऑर्डर दिया गया है; अभी आई नहीं है।

श्री नीतिश्वर प्रसाद सिंह—१० लाख का लोन दिया गया और मशीन खरीदी गई लेकिन वह तो दूसरी जगह भेज दी गई। इससे जाहिर है कि वह कंपनी वहां काम करने नहीं जा रही है। हम कैसे विश्वास करें कि वह काम वहां करेगी जब मशीन खरीद कर दूसरी जगह भेज दी गई ?

अध्यक्ष—अभी तक सरकार से रुपया नहीं दिया गया।

***श्री नीतिश्वर प्रसाद सिंह**—आखिर कहीं से भी रुपया दिया गया और उससे मशीन तो खरीदी गई फिर वह क्यों बाहर भेज दी गई ? मेरा कहना है कि कंपनी को वहां काम करने की मंशा नहीं है।

अध्यक्ष—अच्छा अब आप बैठ जायें।

In my opinion the matter is not so urgent as would justify an adjournment motion to be discussed on the floor of the House. The adjournment motion is, therefore, disallowed.

(अंतराल)

दामोदर घाटी निगम की (१९५१-५२) रिपोर्ट तथा आय-व्ययक (१९५४-५५) पर वाद-विवाद।

DISCUSSION ON THE REPORT (1951-52) AND BUDGET ESTIMATES (1954-55) OF THE DAMODAR VALLEY CORPORATION.

***श्री रामनारायण शर्मा**—अध्यक्ष महोदय, अभी हम दामोदर व्हैली कारपोरेशन के ऐनुयल रिपोर्ट और १९५४-५५ के बजेट एस्टीमेट का विश्लेषण कर रहे हैं और उसके ऊपर जो संशोधन है उनका मैंने समर्थन किया है। मैंने कल्ह बताया कि जहांतक हेडक्वाटर्स को रांची लाने की बात है उसमें हमारी प्रांतीय सरकार भारत सरकार या दामोदर व्हैली कारपोरेशन के सामने इस बात को पूरी मुस्तैदी के साथ रखने में असफल रही है जिसकी वजह से इस असेम्बली का प्रस्ताव रहने के बावजूद भी, और इस बात को बार बार रखने के बावजूद भी कोई फल नहीं हुआ और अभी भी कारपोरेशन का सदर दफ्तर कारपोरेशन के कार्यक्षेत्र से लगभग ३०० मील की दूरी पर है। शायद उनके डाईरेक्टर या दूसरे अधिकारियों को यह आकर्षण होगा कि वे अभी कलकत्ते के जैसे बड़े शहर में रहते हैं और रांची, हजारीबाग या मानभूम के जंगलों में आकर उनको भटकना होगा। तो इस तरह से डी० वी० सी० के सदर दफ्तर का सवाल अभीतक ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, और अपनी सरकार की ओर से जैसा कि माननीय